INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

WWW.CASIRJ.COM
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण का प्रभाव

लोकेश कुमार
सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, उदयपुरवाटी झुन्झुनूं

"भूमण्डलीकरण किसी भी देश के आर्थिक विकास का इंजन है।"

– रॉबर्टसन

सारांश

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को संचार, परिवहन और व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है। इस शब्द का उपयोग कभी–कभी विशेष रूप से आर्थिक वैश्वीकरण के लिए किया जाता है, व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में एक स्थानिक एकीकरण के रूप में वैश्वीकरण जब उन्होंने कहा "वैश्वीकरण को दुनिया भर में सामाजिक संबंधों के गहनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूर के स्थानों को इस तरह से जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं के आकार और इसके विपरीत होते है।

वैश्वीकरण का आम तौर पर अर्थ है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। आरंभ किए गए आर्थिक परिवर्तनों का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ा है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण की भी शुरूआत की। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े संकट में थी जब विदेशी मुद्रा भण्डार घटकर 1 बिलियन डॉलर हो गया। वैश्वीकरण का प्रभाव कृषि, औद्योगिक, वित्तीय, स्वास्थ्य क्षेत्र और कई अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। एलपीजी नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद ही तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास देखा।

शब्दसार

औद्योगिकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, भारीय औद्योगिक नीति, विदेशी निवेश, सामाजिक इक्विटी, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, एल.पी.जी. नीति, अवमूल्यन, विनिवेश, एन. आर.आई. योजना संरचनात्मक समायोजन, अनुदान, क्रेडिट जोखिम, आर्थिक पुनर्निर्माण, ब्रेन ड्रेन, आऊट सोर्सिंग, कॉरर्पोरेट निवेश।

मुख्य विषय

नई आर्थिक नीति का आगमन :

एक बड़े वित्तीय और आर्थिक संकट को झेलने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने एक नई नीति लाई, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति (एलपीजी नीति) के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नई आर्थिक नीति, 1991 के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह संकट से बाहर आने का एक उपाय था। उस समय यही चल रहा था। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और वैश्वीकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे –

1. अवमूल्यन : भुगतान की समस्या के समाधान के लिए भारतीय मुद्रा का 18 से 19% तक अवमूल्यन किया गया।
2. विनिवेश : एलपीजी मॉडल को सुचारू बनाने के लिए कई सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया।
3. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति, एफडीआई को बीमा (26%), रक्षा उद्योगों (26%) आदि जैसे कई क्षेत्रों में अनुमति दी गई थी।
4. एनआरआई योजना : विदेशी निवेशकों को जो सुविधाएं उपलब्ध थीं, वे भी एनआरआई को दी गई।

नई आर्थिक नीति (NEP-1991) ने व्यापार नीतियों, मौद्रिक और वित्तीय नीतियों, राजकोषीय और बजटीय नीतियों और मूल्य निर्धारण और संस्थागत सुधारों के क्षेत्रों में बदलाव पेश किए। NEP-1991 की मुख्य विशेषताएं हैं (1) उदारीकरण (आंतरिक और बाह्य), (2) निजीकरण का विस्तार, (3) सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों को उन क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित करना जहाँ निजी क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना नहीं है, (4) अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, और (5) बाजार के अनुकूल स्थिति।

वैश्वीकरण के परिणाम

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए वैश्वीकरण के निहितार्थ कई हैं। वैश्वीकरण ने विश्व बाजार में अर्थव्यवसाओं के बीच अन्योन्याश्रय और प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है। यह वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार और पूंजी की आवाजाही के संबंध में अंतर निर्भरता में परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप घरेलू आर्थिक विकास पूरी तरह से घरेलू नीतियों और बाजार की स्थितियों से निर्धारित नहीं होते हैं। बल्कि, वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और आर्थिक स्थितियों दोनों से प्रभावित हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, अपनी घरेलू नीति का निर्माण और मूल्यांकन करते समय, शेष विश्व में नीतियों और विकास के संभावित कार्यों और प्रतिक्रियाओं की अनदेखी नहीं कर सकती है। इसने सरकार को उपलब्ध नीति विकल्प को विवश किया जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में कुछ हद तक नीतिगत स्वायत्तता के नुकसान का कारण बनता है।

कृषि क्षेत्र ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जिसके आसपास सामाजिक–आर्थिक विशेषाधकार और अभाव घूमते हैं और इसकी संरचना में किसी भी बदलाव

का सामाजिक इक्विटी के मौजूदा पैटर्न पर एक समान प्रभाव पड़ने की संभावना है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भारत द्वारा अपनाया गया था। एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हुए, भारत ने आईएमएफ से ऋण के लिए संपर्क किया और आईएमएफ ने उसे 'संरचनात्मक समायोजन' ऋण दिया, जो कुछ शर्तों के साथ एक ऋण है जो संबंधित है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए। अनिवार्य रूप से, बाजार (उदारीकरण) के सरकारी नियंत्रण को धीरे–धीरे समाप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (निजीकरण) का निजीकरण करने, और मुक्त व्यापार (वैश्वीकरण) को सक्षम करने के लिए निर्यात सब्सिडी और आयात बाधाओं को कम करने के लिए सुधारों की मांग की गई। वैश्वीकरण ने इसमें मदद की है –

- जीवन स्तर को ऊपर उठाना,
- गरीबी को कम करना,
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- उद्योग और सेवाओं के विस्तार के लिए व्यापक बाजार तैयार करना, और
- राष्ट्रीय आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान देना।

औद्योगिक क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव

भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव तब शुरू हुए जब सरकार ने 1990 के दशक की शुरूआत में देश के बाजारों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। भारतीय उद्योग का वैश्वीकरण अपने विभिन्न क्षेत्रों जैसे इस्पात, दवा, पेट्रोलियम, रसायन, कपड़ा, सीमेंट, खुदरा और बीपीओ में हुआ।

वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्रों के बीच व्यापार अवराधों का निराकरण और वित्तीय प्रवाह के माध्यम से राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार और राष्ट्रों के बीच कॉर्पोरेट निवेश। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष रूप से संचार और परिवहन में तेजी से प्रगति के कारण हाल के वर्षो में दुनिया भर में वैश्वीकरण में वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में बदलाव किया जिसके द्वारा उसने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी।

भारतीय उद्योग में वैश्वीकरण के प्रभावों का लाभ यह है कि कई विदेशी कंपनियां भारत में उद्योग स्थापित करती हैं, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, बीपीओ, पेट्रोलियम, विनिर्माण और रासायनिक क्षेत्रों में और इसने देश के कई लोगों को रोजगार देने में मदद की है। इससे देश में बेरोजगारी और गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली। इसके अलावा भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव का लाभ यह है कि विदेशी कंपनियां अपने साथ अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी लाती हैं और इससे भारतीय उद्योग को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद मिली।

भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव यह हैं कि प्रौद्योगिकी के आने के साथ श्रम की संख्या में कमी आई और इसके परिणामस्वरूप कई लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। यह मुख्य रूप से दवा, रसायन, विनिर्माण और सीमेंट उद्योगों में हुआ।

वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव

आर्थिक क्षेत्र का सुधार आर्थिक उदारीकरण की दिशा में भारत के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हाल के आर्थिक उदारीकरण के उपायों ने हमारे घरेलू बाजार में प्रवेश करने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धियों के द्वार खोल दिए हैं। नवाचार अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया है। वित्तीय मध्यस्थ अपने पारंपरिक दृष्टिकोण से बाहर आ गए हैं और वे अधिक क्रेडिट जोखिमों को मानने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरूप, वैश्विक वित्तीय क्षेत्रों में कई नवाचार हुए हैं जिनका घरेलू क्षेत्र पर भी अपना प्रभाव हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थानों और विनियामक निकायों के उद्‌भव ने वित्तीय सेवा क्षेत्र को रूढ़िवादी उद्योग होने से बहुत गतिशील बना दिया है। इस प्रक्रिया में यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस बदले हुए संदर्भ में, भारत में वित्तीय सेवा उद्योग को देश में फैले लाखों भावी निवेशकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवीन उत्पादों की पेशकश करके आने वाले वर्षों में एक बहुत ही सकारात्मक और गतिशील भूमिका निभानी है। आर्थिक क्षेत्र का सुधार आर्थिक उदारीकरण की दिशा में भारत के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

वित्तीय सेवाओं में वृद्धि (बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाओं को शामिल करते हुए), 2003–04 में 5.6% की गिरावट के बाद 2004–05 में वापस 8.7% और 2005–06 में 10.9% हो गई। 2006–07 में 11.1% की वृद्धि के साा गति को बनाए रखा गया है। वैश्वीकरण के कारण, वित्तीय सेवा उद्योग संक्रमण के दौर में है। बाजार में बदलाव, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी विकास वैश्विक वित्तीय सेवा उद्योग में अभूतपूर्व बदलाव की शुरूआत कर रहे हैं।

निर्यात और आयात पर प्रभाव

वर्ष 2001–02 में भारत का निर्यात और आयात क्रमशः 32,572 और 38362 मिलियन था। कई भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मानित खिलाड़ी बनना शुरू कर दिया है। कृषि निर्यात देश के कुल वार्षिक निर्यात का लगभग 13 से 18% है। 2000–01 में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के कृषि उत्पादों को देश से निर्यात किया गया था, जिनमें से 23% अकेले समुद्री उत्पादों द्वारा योगदान दिया गया था। हाल के वर्षों में समुद्री उत्पाद देश के कुल कृषि निर्यात में एकल सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं, जो कुल कृषि निर्यात का पांचवां हिससा है। अनाज (ज्यादातर बासमती चावल और गैर–बासमती चावल), तेज के बीज, चाय और कॉफी अन्य प्रमुख उत्पाद हैं जिनमें से प्रत्येक देश के कुल कृषि निर्यात में लगभग 5 से 10% की हिस्सेदारी है।

वैश्वीकरण के लाभ

- कंपनियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और उपभोक्ताओं के लिए चुनने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है।
- विकसित देशों से विकासशील देशों में निवेश के प्रवाह में वृद्धि, जिसका उपयोग आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- देशों और अधिक से अधिक सांस्कृतक संपर्क के बीच जानकारी के अधिक से अधिक प्रवाह ने सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में मदद की है।
- तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप विकासशील देशों में ब्रेन ड्रेन का उल्टा

वैश्वीकरण के चुनौतियां

- विकासशील देशों में नौकरियों की आउटसोर्सिंग के परिणामस्वरूप विकसित देशों में नौकरियों का नुकसान हुआ है।
- संचारी रोगों के फैलने का अधिक खतरा है।
- विश्व पर शासन करने वाली अपार शक्ति वाले बहुराष्ट्रीय निगमों का एक अंतर्निहित खतरा है।
- प्राप्त अंत में छोटे विकासशील देशों के लिए, यह अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश के एक सूक्ष्म रूप को जन्म दे सकता है।
- 1987 में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की संख्या 35% से बढ़कर 1999 में 45% हो गई, जो 2005 में 55% हो गई। किसान भूखमरी या आत्महत्या से मर रहे हैं।

अन्य विकासशील देशों के साथ तुलना

वैश्विक व्यापार – पिछले 20 वर्षों में भारत के विश्व व्यापार निर्यात में हिस्सेदारी .05% से बढ़कर 0.7% हो गई है। इसी अवधि में चीन का हिस्सा लगभग 4% हो गया है।

भारत का वैश्विक व्यापार का हिस्सा आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 6 गुना छोटी अर्थव्यवस्था के समान है।

पिछले एक दशक में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह जीडीपी के लगभग 0.5% चीन के लिए 5% और ब्राज़ील के लिए 5.5% है। चीन को मिलने वाला एफडीआई सालाना 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह भारत के मामले में केवल US $ 4 बिलियन है।

निष्कर्ष

भारत ने एलपीजी मॉडल से अत्यधिक प्राप्त किया क्योंकि 2007–2008 में इसका जीडीपी बढ़कर 9.7% हो गया। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। लेकिन वैश्वीकरण के बाद भी, कृषि की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा केवल 17% है। भूमिहीन परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है और किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को देखते

हुए, यह कहा जा सकता है कि बहुत जल्द भारत इन बाधाओं को भी पार कर जाएगा और विकास के अपने मार्ग पर दृढ़ता से मार्च करेगा। हाल के अनुभव का सबक यह है कि किसी देश को सावधानीपूर्वक नीतियों का एक संयोजन चुनना चाहिए जो इसे नुकसान से बचने के लिए अवसर लेने में सक्षम बनाता है। एक सदी से अधिक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है, लेकिन तब से विश्व अर्थव्यवस्था में बड़े विकास हुए है, अमेरिका और यूरोप के अमीर देशों से दो एशियाई दिग्गजों तक ध्यान केन्द्रित करने के लिए अग्रणी – भारत और चीन।

21वीं सदी में दुनिया पर राज करने के लिए अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और दुनिया भर में किए गए विभिन्न अध्ययनों में भारत और चीन की परिकल्पना की गई है। भारत, जो अब क्रय शक्ति समता के मामले में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान से आगे निकल सकता है और 10 वर्षों के भीतर तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। निष्कर्ष निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो आधुनिकीकरण दिखाई देता है, वह वैश्वीकरण का एक योगदान है। वैश्वीकरण का सकारात्मक और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैश्वीकरण ने हमें 1991 से एक लंबा रास्ता तय किया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की उन्नति हुई है।

संदर्भ सूची

- दुबे अभय कुमार : भारत का भूमंडलीकरण
- जैन नीरज : वैश्वीकरण या पुनः औपनिवेशीकरण?
- डॉ. डांगी वंदना : भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप
- खण्डेला मानचन्द : उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
- पुरी वी.के., मिश्र एस.के. गर्ग भारत : भारतीय अर्थव्यवस्था
- सिंह रमेश : भारतीय अर्थव्यवस्था
- लाल एण्ड लाल : भारतीय अर्थव्यवस्था
- सिकेन कुमार : अर्थशास्त्र : वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
- डॉ. माहेश्वरी पी.डी. एवं गुप्ता शीलचन्द्र : भारतीय आर्थिक नीति
- कोली एल.एन. : भारतीय आर्थिक समीक्षा

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM